



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122024-259560
CG-DL-E-20122024-259560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5098]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2024/अग्रहायण 29, 1946

No. 5098]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2024/AGRAHAYANA 29, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5513(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसी अपेक्षा है कि रक्षा स्थापनों के उद्योग में लगी ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 8 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2248(अ), तारीख 12 जून, 2024 द्वारा 24 जून, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा स्थापनों के उद्योग में लगी सेवाओं को 24 दिसंबर, 2024 से छह मास की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/8/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2024

S.O. 5513(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the industry of Defence establishments, which are covered under item 8 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 24th June, 2024 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2248(E), dated the 12th June, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the industry of Defence establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 24th day of December, 2024.

[F. No. S-11017/8/2011-IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.